आर. एन. आई. नं. UPHIN/2010/32566 डाक. पंजीयन. संख्या– SSP/LW/NP-311

अद्भुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक

हर ख़बर पर पैनी नज़र

वर्ष : 17 अंक : 29 लखनऊ, शनिवार 07 नवम्बर 2026 सा 13 नवम्बर 2026 तक पृष्ठ–8 मूल्य : एक रूपया

योगी का बड़ा ऐलानः जल्द 25 हजार शिक्षकों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र, भाई–भतीजावाद पर लगेगा विराम

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित ४,५४३ उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए कहा जल्द ही करीब २५ हजार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने की घोषणा की है। इसके अलावा, दीपावली के ठीक बाद भैयादूज के अगले दिन राजस्व विभाग के १,२०० से अधिक नवचयनित अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश में अब भाई–भतीजावाद नहीं चलेगा। २५ करोड़ जनता ही सरकार का परिवार है और हर युवा को योग्यता व मेरिट के आधार पर समान अवसर मिलेगा। उन्होंने विपक्षी सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले स्थिति यह थी कि आवेदन कोई करता था, परीक्षा कोई और देता था और नौकरी किसी तीसरे को मिल जाती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से युवाओं को नियुक्ति पत्र देना कोई एहसान या ेपा नहीं है, बल्कि यह सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए दावा किया कि वर्ष २०१७ में जब उनकी सरकार बनी थी। तब राज्य कर्मचारियों को समय पर वेतन देने के लिए भी संसाधनों की भारी कमी हुआ करती थी। इसके विपरीत, आज उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी मजबूत है कि जरूरत पड़ने पर वह एक वर्ष तक लगातार अपने कर्मचारियों को वेतन देने का सामर्थ्य रखती है। मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ पुलिस लाइन में नवचयनित अभ्यर्थियों से संवाद करते हुए पूछा कि क्या किसी को चयन के लिए सिफारिश कराने की जरूरत पड़ी, किसी ने लेन–देन या धनराशि का प्रस्ताव दिया अथवा किसी ने धौंस दिखाकर नियुक्ति हासिल करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वर्ष २००३ से २०१७ के बीच हुई



कई भर्तियों में अनियमितताओं के मामले आज भी न्यायालयों में लंबित हैं। योगी ने कहा कि जिन सैफई सिंडीकेट और बेईमान लोगों ने युवाओं के जीवन से खिलवाड़ किया, उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में अकेले पुलिस बल में २.३० लाख अधिकारियों और कार्मिकों की भर्ती पारदर्शी तरीके से की गई है। विभिन्न विभागों में सरकारी भर्तियों की संख्या ६.५ लाख से अधिक हो चुकी है। सरकार ने छह माह में एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का संकल्प लिया है। ४२ हजार होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि पुलिस में ३२ हजार कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर सत्यापन कराया जा रहा है। योगी ने पुलिस सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब ५६ जिलों में आधुनिक बहुमंजिला पुलिस आवास, एक साथ ६० हजार प्रशिक्षुओं की क्षमता वाले प्रशिक्षण केंद्र और हर जिले में साइबर थाना है। सात जिलों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। कार्यक्रम में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, महापौर सुषमा खर्कवाल, विधायकगण, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी कानून–व्यवस्था अमिताभ यश मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने ४,५४३ नवचयनित उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों के अभ्यर्थियों में से १५ को मंच पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनमें अंशु गंगवार, अभय यादव, रवि प्रताप कुशवाहा, प्राची सविता, साक्षी गोंड, रंजीत खरवार, अभिषेक कुमार पाल, अनूप कुमार मौर्य, अजहरुद्दीन खान, निलय मिश्रा, फरहत जहां, श्वेता भदौरिया, आशुतोष राय, अमित कुमार दुबे और मयंक शाक्य शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

६८,५०० शिक्षक भर्ती के आरक्षण विवाद पर जारी, धनतेरस पर भी न्याय की आस में डटे रहे अभ्यर्थी

६७वें दिन भी प्रदर्शन

लखनऊ। लखनऊ के इको गार्डन धरना स्थल पर ६८,५०० सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा–२०१८ की आरक्षण विसंगति के खिलाफ अभ्यर्थियों



का अनवरत प्रदर्शन शुक्रवार को ६७वें दिन भी जारी रहा। धनतेरस जैसे बड़े पर्व पर भी अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी धरने पर डटे रहे। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी ईको गार्डन धरना स्थल के बाहर फव्वारे के पास एकत्रित हुए और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए न्याय की मांग दोहराई। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों की मुख्य मांग है कि ६८,५०० शिक्षक भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षित श्रेणी का पूरा लाभ दिया जाए। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जारी संस्तुतियों के आधार पर भर्ती का संशोधित परिणाम तैयार किया जाए। इसके साथ ही दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके आश्रितों को भी नियमानुसार आरक्षण का लाभ देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। धरने का नेतृत्व कर रहे तूफान सिंह और आशुतोष वर्मा ने कहा कि पिछले ६७ दिनों से सैकड़ों अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। धनतेरस के पावन पर्व पर भी प्रभावित अभ्यर्थियों के घरों में मायूसी और बेरोजगारी का माहौल है। उन्होंने बताया कि कई मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी जा चुकी है और हर जगह से केवल आश्वासन ही मिला है, लेकिन धरातल पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अभ्यर्थियों ने दो टूक कहा कि जब तक सरकार न्यायोचित निर्णय लेते हुए संशोधित परिणाम जारी नहीं करती, तब तक उनका यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। इस दौरान नवीन चौधरी, रंजना जायसवाल, मनोज, राम प्रवेश, विनोद प्रजापति, नसीम फरीदी, दीपक पटेल, रणबहादुर वर्मा, किरण मौर्य, उत्कर्ष पटेल, सुमन यादव, अनुराग पाल, घनश्याम यादव, तारिक, अनश, शिव शंकर गौड़, शिववीर, अजीत और अरविंद समेत सैकड़ों अभ्यर्थी मौजूद रहे।

तीसरी बार ट्रंप पर महाभियोग का खतरा

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की ऐतिहासिक हार के बाद अब ट्रंप के ऊपर महाभियोग का खतरा मंडरा रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रही है। ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं, जिनके ऊपर दो बार महाभियोग चलाया जा चुका है। अब तीसरी बार महाभियोग लाएगा विपक्ष। गौरतलब है कि अमेरिका के निचले सदन में महाभियोग के लिए साधारण बहुमत की जरुरत होती है लेकिन सीनेट में दो तिहाई बहुमत जरूरी होता है। पहले दोनों बार सीनेट में ही ट्रंप के खिलाफ लाया गया महाभियोग प्रस्ताव विफल हुआ था। बहरहाल, नतीजा जो हो लेकिन विपक्ष इस बार ज्यादा गंभीरता से तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी आरोप लगा रही है कि ट्रंप ने अपने पद का इस्तेमाल कर अपने करीबियों को फायदा पहुंचाया और संपत्ति जुटाई। इससे आम लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। डेमोक्रेटिक सांसद रॉबर्ट गार्सिया ने कहा है कि वे यह पता लगाएंगे राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप और उनके परिवार की संपत्ति कैसे बढ़ी। उनका फोकस ट्रंप के बेटों और दामाद जेरेड कुशनर के कारोबारी सौदों पर है। बताया जा रहा है कि डेमोक्रेटिक सांसद गार्सिया ने जांच के लिए पांच मुद्दे तय किए हैं। इनमें ट्रंप परिवार के कारोबारी सौदे, जेफ्री एपस्टीन मामले की जांच में ट्रंप प्रशासन की भूमिका और अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी यानी आईसीई की छापेमारी और कार्रवाई शामिल हैं। इससे पहले खबर आई कि १९६० के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी हाउस अ फ रिप्रेजेंटेटिव्स में सबसे बड़ी जीत दर्ज कर रही है। उसे २६० से ज्यादा सीटें मिलने की संभावना है। सीनेट में भी डेमोक्रेटिक पार्टी बहुमत से आगे निकल चुकी है। बहरहाल, इससे पहले ट्रंप के खिलाफ दो बार महाभियोग चला है। अमेरिकी इतिहास में वे ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं, जिनके खिलाफ दो बार महाभियोग की कार्रवाई हुई। पहली बार ट्रंप पर आरोप था कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की पर दबाव डाला था कि वे जो बाइडेन और उनके बेटे हंटर बाइडेन के खिलाफ जांच का ऐलान करें। ऐसा न करने पर ट्रंप ने यूक्रेन को मिलने वाली करीब ४० करोड़ डॉलर की सैन्य मदद रोक दी थी।

सम्पादकीय

भारतीय उच्च शिक्षाः संस्थानों की संख्या बढ़ी, गुणवत्ता की चुनौती बरकरार

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में लगातार दूसरे वर्ष भारत के किसी भी विश्वविद्यालय को एशिया के शीर्ष ५० संस्थानों में जगह नहीं मिलना देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। यह स्थिति तब है, जब भारत दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा तंत्रों में शामिल है और यहां उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ताजा रैंकिंग में भारत के ३२५ संस्थानों को स्थान मिला है, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या २६४ थी। इस लिहाज से भारत ने संख्यात्मक रूप से अपनी उपस्थिति जरूर मजबूत की है, लेकिन सवाल यह है कि क्या संस्थानों की बढ़ती संख्या के साथ शिक्षा की गुणवत्ता भी उसी अनुपात में बेहतर हो रही है? दुर्भाग्य से इसका जवाब बहुत उत्साहजनक नहीं है। भारत के मुकाबले चीन के ४४८ उच्च शिक्षण संस्थानों को इस सूची में जगह मिली है। शीर्ष १०० संस्थानों में भारत के केवल छह संस्थान शामिल हो सके, जबकि पिछली बार यह संख्या सात थी। इनमें पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान शामिल हैं। यह स्थिति बताती है कि देश के कुछ प्रतिष्ठित संस्थान वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए हैं, लेकिन विश्वविद्यालयों का व्यापक शैक्षणिक परि श्य अभी भी अपेक्षित ऊंचाई हासिल नहीं कर पाया है। आखिर क्या कारण है कि दुनिया में सबसे अधिक युवा आबादी वाले देशों में शामिल भारत का कोई विश्वविद्यालय एशिया के शीर्ष ५० में स्थान नहीं बना पा रहा है? अक्सर क्यूएस जैसी अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग पर सवाल उठाए जाते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि ऐसी सूचियां प्रतिष्ठा सर्वेक्षणों पर काफी निर्भर करती हैं और पहले से प्रसिद्ध संस्थानों को इसका लाभ मिलता है। यह बात कुछ हद तक सही हो सकती है, क्योंकि किसी भी रैंकिंग प्रणाली की अपनी सीमाएं और मूल्यांकन संबंधी पूर्वाग्रह हो सकते हैं। लेकिन केवल इन सीमाओं का हवाला देकर अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। किसी आईने में तस्वीर अच्छी न दिखे तो आईने को दोष देने के बजाय अपनी सूरत सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। क्यूएस रैंकिंग में केवल संस्थानों की लोकप्रियता को आधार नहीं बनाया जाता। इसमें शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ताओं के बीच संस्थान की साख, शोध की गुणवत्ता और उसका प्रभाव, शिक्षक–छात्र अनुपात, अंतरराष्ट्रीय शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की मौजूदगी तथा स्नातकों को रोजगार मिलने जैसे महत्वपूर्ण मानदंड भी शामिल होते हैं। ये ऐसे पैमाने हैं, जिनका किसी भी विश्वविद्यालय की वास्तविक शैक्षणिक क्षमता से सीधा संबंध है। आखिर शोध की गुणवत्ता, विद्यार्थियों को मिलने वाली शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने की जरूरत से कौन इनकार कर सकता है? भारत में उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए पिछले कुछ दशकों में अनेक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और तकनीकी संस्थान स्थापित किए गए हैं। लेकिन केवल संस्थानों की संख्या बढ़ा देने से शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं होती। इसके लिए योग्य शिक्षकों की पर्याप्त नियुक्ति, आधुनिक प्रयोगशालाएं, बेहतर पुस्तकालय, शोध के लिए पर्याप्त बजट और उद्योगों के साथ शैक्षणिक संस्थानों का प्रभावी तालमेल जरूरी है। कई विश्वविद्यालय आज भी शिक्षकों के रिक्त पदों, संसाधनों की कमी और पुराने पाठ्यक्रमों जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में उनसे वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद करना व्यावहारिक नहीं होगा। एक बड़ी समस्या शोध ा के प्रति अपेक्षित गंभीरता का अभाव भी है। दुनिया के अग्रणी विश्वविद्यालय केवल डिग्रियां बांटने वाले संस्थान नहीं हैं, बल्कि वे नए विचारों, तकनीकों और आविष्कारों के केंद्र हैं। वहां शोध को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता, अकादमिक स्वतंत्रता और प्रतिभाशाली शोधार्थियों को बेहतर अवसर दिए जाते हैं। भारत में भी प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर का शोध वातावरण उपलब्ध कराने की चुनौती बनी हुई है। इसके कारण कई मेधावी विद्यार्थी बेहतर शिक्षा और शोध के अवसरों के लिए विदेशों का रुख करते हैं। सरकार को उच्च शिक्षा के बजट और नीतियों में गुणवत्ता को प्राथमिकता देनी होगी। विश्वविद्यालयों को केवल परीक्षा परिणाम और डिग्रियों की संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि शोध, नवाचार, रोजगार और सामाजिक उपयोगिता के आधार पर भी आंका जाना चाहिए। निजी और सरकारी संस्थानों के बीच गुणवत्ता का अंतर कम करना भी आवश्यक है। साथ ही विश्वविद्यालयों को राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप से मुक्त रखते हुए शैक्षणिक स्वतंत्रता और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित करनी होंगी। ३२५ संस्थानों की मौजूदगी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन जब तक उनके बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शोध और नवाचार की संसेंति विकसित नहीं होगी, तब तक यह उपलब्धि अधूरी रहेगी। जरूरत रैंकिंग पर सवाल उठाने की नहीं, बल्कि उन कसौटियों पर खरा उतरने की है, जो किसी विश्वविद्यालय को वास्तव में विश्वस्तरीय बनाती हैं। संस्थानों की संख्या में वृद्धि पर्याप्त नहीं है। भारत को उच्च शिक्षा में शोध, नवाचार, रोजगारपरकता और शैक्षणिक गुणवत्ता को प्राथमिकता देनी होगी।

अग्निपथ योजनाः दो साल का विस्तार नहीं, अग्निवीरों को चाहिए भविष्य की सुरक्षा

भारतीय सेना में अग्निवीरों की सेवा अवधि दो साल और बढ़ाने की संभावित व्यवस्था को पहली नजर में उनके लिए राहत भरा कदम माना जा सकता है। चार साल की सेवा पूरी होने के बाद रोजगार और भविष्य को लेकर अनिश्चितता से जूझ रहे अग्निवीरों को इससे कुछ अतिरिक्त समय जरूर मिल सकता है, लेकिन



राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य व्यवस्था के व्यापक नजरिये से यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। सवाल केवल अग्निवीरों की नौकरी दो साल बढ़ाने का नहीं, बल्कि सेना की सेवा शर्तों, सैनिकों के भविष्य और सैन्य क्षमता को लेकर सरकार की दीर्घकालिक नीति का है। बताया जा रहा है कि अग्निवीरों के कार्य रिक र्ड और प्रदर्शन के आधार पर उनकी सेवा अवधि बढ़ाने का विकल्प दिया जा सकता है। लेकिन इससे कई बुनियादी सवालों का जवाब नहीं मिलता। क्या सेवा विस्तार पाने वाले अग्निवीरों को स्थायी सैनिकों के समान वेतन और सुविधाएं मिलेंगी? क्या उन्हें पेंशन, अवकाश, चिकित्सा सुविधा और सेवानिवृत्ति के अन्य लाभ प्राप्त होंगे? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि देश की रक्षा करते हुए किसी अग्निवीर के शहीद होने की स्थिति में उसके परिवार को किस तरह की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी? जब तक इन सवालों पर स्पष्ट नीति नहीं बनती, तब तक सेवा विस्तार को केवल अस्थायी राहत ही माना जाएगा। अग्निपथ योजना की घोषणा के समय से ही इसके औचित्य और दूरगामी परिणामों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इस योजना के तहत सेना में भर्ती की एक ऐसी व्यवस्था लागू की गई, जिसमें चार साल की सेवा के बाद अधिकतम २५ प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सेवा में शामिल करने का प्रावधान है, जबकि शेष ७५ प्रतिशत को सेवा से मुक्त कर दिया जाता है। इसका अर्थ है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने और सैन्य अनुशासन में ढलने के बाद भी अधिकांश युवाओं के सामने भविष्य में रोजगार की चुनौती बनी रहती है। अब यदि सेवा विस्तार का विकल्प सामने आता है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सरकार को मूल योजना की खामियों का पहले से अंदाजा नहीं था? अग्निपथ योजना के समर्थकों का तर्क है कि इससे सेना की औसत आयु कम होगी, युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी और रक्षा बजट पर पेंशन का बोझ घटेगा। यह भी कहा जाता है कि कम उम्र के सैनिक शारीरिक रूप से अधिक सक्षम होंगे और आधुनिक युद्ध की जरूरतों के अनुरूप सेना को तैयार करने में मदद मिलेगी। इन तर्कों की अपनी अहमियत है, लेकिन सैन्य सेवा को केवल बजट बचाने की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता। सेना की सबसे बड़ी ताकत उसके जवानों का मनोबल, अनुभव, प्रशिक्षण और संस्थागत अनुशासन होता है। युद्ध जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वर्षों का अनुभव और सैन्य कौशल निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भारत की सुरक्षा चुनौतियां भी किसी से छिपी नहीं हैं। जम्मू–कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण परिस्थितियां बनी रहती हैं। ऐसे में सेना को केवल युवा सैनिकों की जरूरत नहीं, बल्कि अनुभवी और प्रशिक्षित जवानों की भी आवश्यकता है। आधुनिक हथियारों के संचालन, सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनाती और कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने के लिए लंबे अनुभव का अपना महत्व है। इसलिए भर्ती व्यवस्था में बदलाव करते समय सैन्य विशेषज्ञता और युद्धक क्षमता को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अग्निपथ योजना लागू होने के कुछ ही वर्षों के भीतर उसमें सेवा विस्तार जैसे विकल्पों पर विचार की जरूरत पड़ना उसके मूल ढांचे की समीक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यदि सेना को प्रशिक्षित जवानों की सेवाएं लंबे समय तक चाहिए, तो उनके लिए स्पष्ट और सम्मानजनक सेवा शर्तें तय होनी चाहिए। केवल दो साल का विस्तार देकर रोजगार की अनिश्चितता को टालना युवाओं की समस्याओं का समाधान नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह अग्निपथ योजना की व्यापक समीक्षा कर सेना की जरूरतों, युवाओं के भविष्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करे। स्थायी भर्ती व्यवस्था के विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। देश की रक्षा करने वाले जवानों को अस्थायी नौकरी की चिंता से मुक्त रखना सरकार की जिम्मेदारी है। आखिर जिस युवा से देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने की अपेक्षा की जाती है, उसे अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए अनिश्चितता में क्यों रखा जाए? सैनिक का मनोबल केवल हथियारों से नहीं, बल्कि उसके सम्मान, अधिकारों और सुरक्षित भविष्य से भी मजबूत होता है।

ऑनलाइन कारोबारी से ६.८५ लाख रुपये ऐंठे, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जांच शुरू

सुलतानपुर। सुलतानपुर के नगर कोतवाली क्षेत्र के विनोबापुरी निवासी कारोबारी राम नारायण पांडेय से साइबर अपराधियों ने ६ लाख ८५ हजार रुपये ठग लिए हैं। आरोप है कि अज्ञात ठगों ने उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचाने का भय दिखाकर यह रकम ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत में राम नारायण पांडेय (पुत्र द्वारिका प्रसाद पांडेय) ने बताया कि उनके साथ अ नलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की गई है। अपराधियों ने उन्हें और उनके परिवार को नुकसान या चोट पहुंचाने का डर दिखाया और ऐसी परिस्थितियां पैदा कीं कि वे भारी रकम देने के लिए विवश हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने तुरंत पुलिस से संपर्क कर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली है और इस मामले की विवेचना निरीक्षक जय प्रकाश सिंह को सौंपी गई है, जो विभिन्न पहलुओं से इसकी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति की धमकी या अनुचित दबाव में आकर पैसे ट्रांसफर बिल्कुल न करें। पुलिस, सीबीआई या अन्य जांच एजेंसियों के नाम पर डराने–धमकाने वालों से हमेशा सतर्क रहें। किसी भी संदिग्ध कॉल या अ नलाइन ध ामकी मिलने पर तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दें। साइबर ध ोखाधड़ी का शिकार होने पर तत्काल राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर १९३० पर कॉल करें और आधि ाकारिक पोर्टल **cybercrime-gov-in** पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

जानकीपुरम में रू१२ करोड़ से बनेगी तीन मंजिला आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी, महापौर सुषमा खर्कवाल ने किया शिलान्यास

लखनऊ। लखनऊ नगर निगम द्वारा शहर में शैक्षिक एवं सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की जा रही है। अवस्थापना निधि के



अंतर्गत जानकीपुरम प्रथम वार्ड में सेक्टर–एफ, इंजीनियरिंग कॉलेज के निकट ध्१२ करोड़ की लागत से तीन मंजिला पब्लिक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाएगा। महापौर श्रीमती सुषमा खर्कवाल जी ने विधिवत भूमि पूजन एवं शिलान्यास कर परियोजना की शुरुआत की। शिलान्यास कार्यक्रम में स्थानीय पार्षद श्रीमती निशा तिवारी जी, मंडल अध्यक्ष श्री संजय तिवारी जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री राकेश पाण्डेय जी, मंडल उपाध्यक्ष श्रीमती दिव्यांशी शुक्ला जी, अपर नगर आयुक्त श्री अरुण कुमार गुप्त जी, मुख्य अभियंता श्री महेश वर्मा जी, पर्यावरण अभियंता श्री संजीव प्रधान जी, मंच संचालक श्री सौरभ तिवारी जी सहित नगर निगम के अधिकारी–कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। करीब एक एकड़ क्षेत्रफल में बनने वाली इस तीन मंजिला लाइब्रेरी को आधुनिक शैक्षिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें डिजिटल माध्यम से अध्ययन की सुविधा के साथ विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अलग–अलग स्थान तैयार किए जाएंगे। परियोजना के अंतर्गत बच्चों के लिए विशेष रीडिंग जोन और शैक्षिक एवं बौद्धिक गतिविधियों के लिए सेमिनार ह ल बनाया जाएगा। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग हॉल की व्यवस्था होगी। लाइब्रेरी में कैफेटेरिया तथा लगभग ५० वाहनों की पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस आधुनिक लाइब्रेरी के निर्माण से जानकीपुरम सहित आसपास के क्षेत्रों के छात्र–छात्राओं और युवाओं को अध्ययन के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध होगा। डिजिटल संसाधनों के माध्यम से उन्हें ज्ञान एवं सूचना के विभिन्न माध्यमों तक पहुंच मिलेगी। वहीं, सेमिनार हॉल और अन्य सुविधाओं के माध्यम से शैक्षिक एवं सामुदायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस, इंजीनियरिंग क लेज और ड . एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) के आसपास रहने वाले विद्यार्थियों को इस डिजिटल लाइब्रेरी से विशेष लाभ मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र–छात्राओं को अध्ययन के लिए बेहतर वातावरण, डिजिटल संसाधन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

लखनऊ की सीबीआई अदालत से बबलू श्रीवास्तव को बड़ी राहत, पुराने अपहरण मामले में हुए दोषमुक्त

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चर्चित मामलों में एक बड़े घटनाक्रम के तहत, अंडरवर्ल्ड ड न ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव को एक पुराने अपहरण मामले में अदालत से बड़ी राहत मिली है। लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाते हुए बबलू श्रीवास्तव को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत द्वारा पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव और अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप सिद्ध न कर पाने के कारण यह फैसला आया है। लंबे समय से विभिन्न मामलों के चलते जेल की सलाखों के पीछे बंद रहे बबलू श्रीवास्तव के लिए इस फैसले को एक बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है। अदालत के इस निर्णय के बाद उनके वकीलों और समर्थकों ने राहत की सांस ली है। इस



मामले में कोर्ट के विस्तृत आदेश और अन्य तकनीकी पहलुओं की प्रतीक्षा की जा रही है, लेकिन इस फैसले से न्यायिक हलकों में खासी चर्चा है।

दीपावली–छठ पर रेलवे का बड़ा इंतजाम, ५४ जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलेंगीय ३८६ सीसीटीवी से होगी निगरानी

लखनऊ। दीपावली और छठ पूजा पर घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने विशेष इंतजाम किए हैं। त्योहारों के दौरान मंडल के स्टेशनों से ५४ जोड़ी स्पेशल ट्रेनें कुल १,७०४ फेरों में गुजरेंगी। जरूरत पड़ने पर १० अतिरिक्त टीओडी स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया, अतिरिक्त शेल्टर और निगरानी की व्यवस्था की गई है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पीआरएस भवन में होल्डिंग एरिया बनाया गया है। इसके अलावा प्लेटफॉर्मों पर २६ अस्थायी शेल्टर तैयार किए गए हैं। स्टेशन पर सात अतिरिक्त रेक उपलब्ध रहेंगे। वहीं, आठ नियमित ट्रेनों में एक–एक अतिरिक्त शयनयान कोच लगाया जा रहा है। वाराणसी जंक्शन पर ४०० से ५०० यात्रियों की क्षमता वाला होल्डिंग एरिया विकसित किया जा रहा है। अयोध्या धाम और अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशनों पर भी २,५००–२,५०० यात्रियों की क्षमता वाले होल्डिंग एरिया प्रस्तावित हैं। रेलवे की योजना के मुताबिक, नौ से १३ नवंबर के बीच जरूरत के अनुसार १० टीओडी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के लिए लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या धाम स्टेशनों पर कुल ३८६ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आरपीएफ के जवान भी अलग–अलग शिफ्ट में तैनात रहेंगे। लखनऊ और वाराणसी में ४५–४५ आरपीएफ जवान प्रति शिफ्ट तैनात रहेंगे। अयोध्या धाम स्टेशन पर प्रति शिफ्ट १७ जवान सुरक्षा संभालेंगे। बैगेज स्कैनर समेत अन्य सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। टिकट लेने में यात्रियों की सुविधा के लिए लखनऊ में २३, वाराणसी में २४ और अयोध्या के दोनों स्टेशनों पर सात–सात एटीवीएम यानी स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं। अयोध्या में रेलवन ऐप से टिकट बुकिंग के लिए १५–१५ मोबाइल क्यूआर कोड भी लगाए गए हैं। मंडल में २४ घंटे



वार रूम से निगरानी की जाएगी। यात्रियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर १३६ और रेल मदद सेवा उपलब्ध रहेगी। वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। दिवाली पर दिल्ली और मुंबई से लखनऊ आने वाले यात्रियों की भीड़ शुक्रवार से बढ़ने की उम्मीद है। इस बीच तत्काल टिकटों के लिए यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शुक्रवार की यात्रा के लिए गुरुवार सुबह १० बजे से तत्काल कोटे में सीट बुक कराने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन महज तीन मिनट में ४६८ सीटें बुक हो गईं। दिल्ली से आने वाली एसी एक्सप्रेस, लखनऊ मेल, गोमती और कैफियात एक्सप्रेस के साथ मुंबई से आने वाली पुष्पक और कुशीनगर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में तत्काल कोटे की सीटें कुछ ही मिनटों में खत्म हो गईं। इससे त्योहार पर घर लौटने की तैयारी कर रहे कई यात्रियों को निराशा हाथ लगी।

दिव्यांगों के हुनर ने सजाई दिव्य दीपावली, जवाहर भवन मेले में कलाकृतियों की खूब हुई खरीदारी

लखनऊ। हुनर को जब मंच मिला तो दिव्यांगों के हाथों से निकली कलाकृतियों ने हर किसी का दिल जीत लिया। किसी ने ऊन और तार से कमल के फूल जैसे खूबसूरत आसन बनाए तो किसी ने गोबर और चूड़ियों से रंग–बिरंगे दीये तैयार किए। भगवान की चरण पादुका से लेकर सजावटी सामान तक ने लोगों को खूब आकर्षित किया। मौका था गुरुवार को जवाहर भवन में आयोजित 'दिव्य दीपावली मेला–२०२६' का, जहां दिव्यांगों के हुनर को न सिर्फ सराहना मिली, बल्कि उनके बनाए उत्पादों की जमकर खरीदारी भी हुई दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से आयोजित इस राज्य स्तरीय मेले में नौ विभागीय संस्थाओं और १६ स्वैच्छिक संस्थाओं ने अपने स्टॉल लगाए। यहां दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों ने हस्तशिल्प, पारंपरिक दीपक, मोमबत्तियां, पूजन सामग्री, फूल–मोतियों की झालरें और घरेलू उपयोग की वस्तुओं का प्रदर्शन और बिक्री की। मेले का उद्घाटन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने किया। उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर कारीगरों से बातचीत की और उनके हुनर की सराहना की। मेले में प्रयास महाविद्यालय के छात्रों की बनाई कलाकृतियां खास आकर्षण रहीं। छात्रों ने ऊन और तार की मदद से रंग–बिरंगे कमल के फूल के आकार के आसन तैयार किए थे। इनकी कीमत २५० रुपये रखी गई थी। वहीं, चूड़ी के स्टैंड पर सजाए गए रंगीन गोबर के दीयों ने भी लोगों का ध्यान खींचा। इन दीयों की कीमत महज २० रुपये थी। संस्था की प्रभारी विजय



लक्ष्मी ने बताया कि छात्रों ने मेहनत और रचनात्मकता से इन उत्पादों को तैयार किया है। सेवा संकल्प संस्था के दिव्यांग कारीगरों ने भी अपने नवाचार से लोगों को प्रभावित किया। संस्था ने गोबर से बने दीये, भगवान की मूर्तियां और सजावटी व पूजन सामग्री प्रदर्शित की। संस्था की रंजना तिवारी ने बताया कि इस बार दिव्यांग कारीगरों ने कुछ नया करने की कोशिश की है। उन्होंने कांच के ब क्स में गाय के गोबर से भगवान की चरण पादुका तैयार की है। इसकी कीमत ४०० से ५०० रुपये रखी गई है। आकर्षक बनावट और सजावट के चलते यह उत्पाद लोगों के बीच खासा लोकप्रिय रहा। उद्घाटन के दौरान प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि दिव्यांगजन अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम हैं। जरूरत सिर्फ उन्हें उचित अवसर, मंच और बाजार उपलब्ध कराने की है। ऐसे आयोजन उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन दया के नहीं, बल्कि समाज में समान भागीदारी, सम्मान और अवसर के अधिकारी हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि इस दीपावली पर दिव्यांगजनों के हाथों से तैयार उत्पाद खरीदें, ताकि उनके हुनर को प्रोत्साहन मिलने के साथ उनकी आजीविका भी मजबूत हो। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी शशांक सिंह ने बताया कि मेले का उद्देश्य दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच उपलब्ध कराना है। इससे उन्हें अपने उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार मिलेगा और वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगे। कार्यक्रम में विभाग के अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

यूजीसी के समानता संबंधी नए नियमों पर फिर होगा विचार, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कमेटी बनाने के दिए संकेत

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता बढ़ाने के मकसद से जो दिशानिर्देश जारी किए थे, उन पर नए सिरे से विचार के लिए एक कमेटी बनाने पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार, पांच नवंबर को सुनवाई में सरकार ने कहा कि यूजीसी ने इस साल जनवरी में जो दिशानिर्देश जारी किए हैं उन पर पुनर्विचार होगा और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी के साथ भेदभाव न हो। गौरतलब है कि यूजीसी की ओर से जारी दिशानिर्देशों सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए बहुत भेदभाव वाले थे। इसलिए इनका व्यापक विरोध हुआ। विवाद बढ़ने पर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां अदालत ने इस रोक लगा दी। गुरुवार को इस पर सुनवाई हुई, जिसके दौरान स लिसीटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ज यमाल्य बागची की पीठ को बताया, 'सरकार इस मामले की जांच कर रही है ताकि छात्रों की चिंताओं का समाधान हो सके और कोई भी वर्ग असंतुष्ट या आशंकित महसूस न करे'। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने हर छात्र के हितों की रक्षा करने की जरुरत पर जोर दिया। इसके बाद अदालत ने याचिकाओं की इस सुनवाई को चार सप्ताह के लिए टाल दिया है। गौरतलब है कि



यह मामला 'अबेदा सलीम तडवी बनाम भारत संघ' और इससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित है। २०१६ में यह याचिका रोहित वेमुला और पायल तडवी की माताओं ने दायर की थी। आरोप है कि इन दोनों ने कैम्पस में जातिगत भेदभाव का सामना करने के बाद खुदकुशी कर ली थी। इनकी याचिका में उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव के खिलाफ मजबूत सुरक्षा उपायों की मांग की गई थी। इसके बाद यूजीसी ने इस साल जनवरी में २०२६ नए नियमों को अधिसूचित किया था। इससे पहले २०१२ के नियम लागू थे। विवाद बढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने २०२६ के नियमों पर रोक लगा दी। कोर्ट ने इन नियमों को लेकर कहा था कि ये नियम पहली नजर में अस्पष्ट लगते हैं और इनका दुरुपयोग हो सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जब तक नए नियम नहीं बन जाते, तब तक २०१२ के नियम लागू रहेंगे। केंद्र सरकार ने अगस्त २०२६ में भी कोर्ट को बताया था कि इन नियमों पर फिर से विचार किया जा रहा है। गौरतलब है कि यूजीसी के दिशानिर्देशों के बाद सामान्य वर्ग भाजपा से नाराज है। सोशल मीडिया में इस वर्ग के राइटविंग समर्थक भी खुल कर भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं। हाल में बिहार और उत्तर प्रदेश में हुए एमएलसी चुनावों में भाजपा के खराब प्रदर्शन के पीछे सामान्य वर्ग की नाराजगी को एक कारण बताया जा रहा है। ध्यान रहे तीन महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। तभी ऐसा माना जा रहा है कि यूजीसी की ओर से जारी दिशानिर्देशों में बदलाव की पहल उस मजबूरी में हो रही है।

दहेज में कार की मांग बनी मुसीबत, विवाहिता से मारपीट करने वाले चार दोषियों को सजा

हरदोई। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को प्रताड़ित करने और घर से बाहर निकालने के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) ऋचा वर्मा की अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने दोष साबित होने पर पति समेत चार अभियुक्तों को दहेज उत्पीड़न, मारपीट और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत एक वर्ष की कैद और कुल ११,००० रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि, जान से मारने की धमकी के आरोप में पर्याप्त सबूत न मिलने पर अदालत ने उन्हें उस धारा से दोषमुक्त कर दिया है। अभियोजन पक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वादिनी ऊषा वर्मा का विवाह ७ फरवरी २०१५ को बब्लू उर्फ नरेश के साथ हुआ था। शादी के कुछ समय बाद ही पति बब्लू, देवर आशीष कुमार उर्फ सोनू, ससुर रामऔतार और ननद रंजना उर्फ कल्पना अतिरिक्त दहेज के रूप में चार पहिया वाहन की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर विवाहिता को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। इसके बाद पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाते हुए २५ मार्च २०१८ को संडीला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों का बारीकी से परीक्षण किया। इसके बाद बब्लू, आशीष कुमार उर्फ सोनू, रामऔतार और रंजना उर्फ कल्पना को दोषी करार दिया। अदालत ने सभी अभियुक्तों को एक वर्ष के कारावास और ११ हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।

रूस का यूक्रेन पर हमला

नई दिल्ली। रूसी सेना ने गुरुवार रातभर यूक्रेन की ऊर्जा सुविध ाओं और यूक्रेनी सेना की मदद में इस्तेमाल किए जाने वाले मालवाहक जहाजों पर हमले किए। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। मंत्रालय के अनुसार इन हमलों में कीव क्षेत्र के बिला त्सेरकवा में स्थित बैटरी भंडारण केंद्र को निशाना बनाया गया। ओडेसा बंदरगाह पर यूक्रेन के लिए दोहरे इस्तेमाल का सामान लेकर जा रहे एक सूखा मालवाहक जहाज पर भी हमला किया गया है। इससे पहले रूसी सशस्त्र बलों ने ओडेसा क्षेत्र में यूक्रेनी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बंदरगाह के बुनियादी ढांचे और सैन्य उपयोग से जुड़ा सामान ले जाने वाले समुद्री जहाजों पर ड्रोन हमले जारी रखे थे।

हिरासत के बाद २४ घंटे में पेश करना होगा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में लेने, गिरफ्तार करने और अदालत में पेश करने के समय को लेकर सालों से बनी अस्पष्टता को दूर कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने के बाद २४ घंटे के भीतर अदालत में पेश करना होगा। इस समय सीमा में किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले यह व्याख्या की जाती थी कि हिरासत में रखने की अवधि अलग है और २४ घंटे की समय सीमा एफआईआर दर्ज करके औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने के बाद शुरू होती है। इसे स्पष्ट करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की २४ घंटे की समय सीमा उसे हिरासत में लेते ही शुरू हो जाएगी। यह समय औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज होने के समय से नहीं गिना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'जांच एजेंसियां किसी व्यक्ति को पहले हिरासत में लेकर बाद में उसकी गिरफ्तारी दर्ज करने का रास्ता नहीं अपना सकतीं'। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला गिरफ्तार त्रिपुरा के चार लोगों की याचिका से जुड़ा है। इनका आरोप है कि हिरासत में लेने और गिरफ्तारी दर्ज करने के बीच करीब २१ घंटे का अंतर था। इस मामले की सुनवाई जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस अतुल एस चंद्रकुर की बेंच में हुई।

एएमयू छात्रसंघ चुनाव में महिलाओं का ऐतिहासिक दबदबा, १०५ साल में पहली बार नशरा नईम बनीं उपाध्यक्षय छह पदों पर महिला प्रत्याशियों की जीत

अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के छात्रसंघ चुनाव में इस बार महिला प्रत्याशियों ने नया इतिहास रच दिया है। विश्वविद्यालय के १०५ साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला ने छात्रसंघ उपाध्यक्ष का पद हासिल किया है। नशरा नईम ने ७,०६१ वोट पाकर यह उपलब्धि अपने नाम की। इतना ही नहीं, चुनाव में कुल १३ पदों में से छह पर महिला प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। शुक्रवार को चुनाव परिणाम घोषित किए गए। जहां नोमान अशरफ अध्यक्ष और मो. हमदान ने सचिव के पद पर जीत हासिल की। उपाध्यक्ष पद के चुनाव में नशरा नईम को ७,०६१ वोट मिले, जबकि उनकी निकटतम प्रतिद्वंद्वी को ५,८१८ मत हासिल हुए। इस तरह नशरा ने १,२७३ वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के इतिहास में पहली बार किसी महिला को उपाध्यक्ष चुना गया है। वहीं, अध्यक्ष पद पर मोहम्मद नोमान अशरफ ने ४,१०० से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की। मोहम्मद हमदान छात्रसंघ के सचिव चुने गए। इस बार एएमयू छात्रसंघ चुनाव कई



मायनों में खास रहे। विश्वविद्यालय में करीब आठ साल के अंतराल के बाद चुनाव कराए गए। इससे पहले पिछले तीन वर्षों से छात्र लगातार विरोध–प्रदर्शन कर रहे थे। एक वरिष्ठ संकाय सदस्य के मुताबिक, जेन–जी के विरोध–प्रदर्शनों का असर भी इस बार के चुनाव पर दिखाई दिया। उन्होंने बताया कि पहले जहां चुनाव प्रचार में विश्वविद्यालय परिसर से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहते थे, वहीं इस बार राष्ट्रीय मुद्दों और मुस्लिम समुदाय से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। चुनाव परिणाम एएमयू छात्रसंघ और विश्वविद्यालय कोर्ट चुनाव के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. जावेद तालिब तथा महिला क लेज छात्रसंघ चुनाव की मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. नाजिया हसन ने घोषित किए। कुलपति प्रो. नईमा खातून ने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होने पर खुशी जताई। उन्होंने इसे विश्वविद्यालय की लोकतांत्रिक परंपराओं की जीत बताया। साथ ही चुनाव में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और प्रतिनिधित्व का स्वागत करते हुए महिला सशक्तिकरण के महत्व पर जोर दिया। विश्वविद्यालय अधिकारियों के मुताबिक, चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा की कोई घटना सामने नहीं आई।

जंतर मंतर मामले में कम शिकायतें मिलीं

नई दिल्ली। पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर क करोच जनता पार्टी की ओर से किए गए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की जांच कर रही कमेटी को ज्यादा शिकायतें नहीं मिल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जंतर मंतर पर २० जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान हिंसा और पुलिस की ज्यादती की जांच कर रही कमेटी को अब तक बहुत कम शिकायतें मिली हैं। अदालत ने कहा है कि पर्याप्त सामग्री नहीं होने के कारण कमेटी फिलहाल किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त कमोटी बनाई है। इस कमेटी ने कोर्ट को बताया कि शिकायतों के लिए पोर्टल और ईमेल की व्यवस्था करने के बावजूद लोगों ने बहुत कम शिकायतें दर्ज कराईं। यह भी बताया गया है कि २६ अक्टूबर को कमेटी की बैठक में सिर्फ एक शिकायतकर्ता हलफनामे के साथ पहुंचा था, जबकि इस बैठक की जानकारी काफी पहले सार्वजनिक कर दी गई थी और लोगों से शिकायतों के साथ पहुंचने की अपील की गई थी। बहरहाल, गुरुवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पीड़ितों की ओर से दाखिल वीडियो, याचिकाएं और हलफनामे कमेटी को भेजने की अनुमति दी। साथ ही निर्देश दिया कि कमेटी संबंधि ात पक्षों से जवाब लेकर नियमित अंतराल पर अंतरिम रिपोर्ट पेश करे। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, १३ अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराने के लिए अ नलाइन पोर्टल शुरू किया गया था। इस पर शिकायतकर्ता को नाम, आध ार नंबर या दूसरी पहचान संबंधी जानकारी देना जरूरी नहीं है। इतना ही नहीं कमेटी ने देश भर के १४६ अखबारों में सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित कर शिकायतें आमंत्रित की थीं। ईमेल, डाक और कार्यालय में सीधे शिकायत देने की सुविधा भी रखी गई थी। फिर भी बहुत कम शिकायतें मिली हैं।

छह राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का आदेश

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) का आदेश दिया है। इसके लिए एक जनवरी, २०२७ को अर्हता तिथि निर्धारित की गई है, जबकि अंतिम मतदाता सूची २१ जनवरी को प्रकाशित की जाएगी। इस प्रक्रिया के दायरे में अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम शामिल हैं। यह कदम मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण को लेकर जारी राजनीतिक विवाद और विपक्ष के बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोपों के बीच उठाया गया है। आयोग ने बुधवार को जारी आदेश में छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों (सीईओ) को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २१ के तहत पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। इसमें विशेष रूप से उन पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने पर जोर दिया गया है, जिनके नाम अब तक दर्ज नहीं हैं। इनमें युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाता प्रमुख रूप से शामिल हैं। आयोग के चार नवंबर के पत्र के अनुसार, मतदान केंद्रों का युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्थापन २० नवंबर तक पूरा किया जाएगा। एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची ३० नवंबर को प्रकाशित होगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि ३० नवंबर से ३० दिसंबर तक रहेगी। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को १६ जनवरी तक सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा करना होगा। इसके बाद २१ जनवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक निरंतर बनाने के उद्देश्य से आयोग ने एक महत्वपूर्ण प्रावधान के तहत उन लोगों से अग्रिम आवेदन स्वीकार करने की अनुमति भी दी है, जो एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर, २०२७ को १८ वर्ष की आयु पूरी करेंगे। इन आवेदनों पर संबंधित तिमाही में ही कार्रवाई की जाएगी, जब आवेदक मतदान के लिए पात्र होंगे। जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) जारी है या हाल ही में पूरा हुआ है, वहां एसएसआर तत्काल शुरू नहीं किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, नगालैंड, दिल्ली, त्रिपुरा और तेलंगाना शामिल हैं। आयोग ने कहा है कि इन क्षेत्रों के लिए अलग से कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। हिमाचल



प्रदेश, जम्मू–कश्मीर और लद्दाख में भी पुनरीक्षण का कार्यक्रम बाद में घोषित होगा, जहां एसआईआर अभी शुरू नहीं हुआ है। इन क्षेत्रों में मौसम की स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। निर्वाचन अधिकारियों को सभी पात्र लेकिन अब तक पंजीकरण से वंचित नागरिकों, एक जनवरी, २०२७ तक १८ वर्ष की आयु पूरी करने वालों और वर्ष के दौरान बाद की तीन अर्हता तिथियों पर पात्र होने वाले संभावित मतदाताओं से आवेदन प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा गया है। मौजूदा मतदाता प्रविष्टियों को हटाने के संबंध में आयोग ने विस्तृत सुरक्षा उपाय निर्धारित किए हैं, ताकि किसी का नाम मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सके। कथित दोहरी प्रविष्टियों, मृत मतदाताओं और स्थायी रूप से निवास स्थान बदल चुके लोगों के मामलों में मौके पर सत्यापन अनिवार्य होगा। किसी मतदाता का नाम हटाने का प्रस्ताव होने पर संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के बाद कारणों सहित आदेश पारित करना होगा। यह प्रक्रिया लागू कानूनी प्रावधानों के अधीन होगी। ऐसे आदेश ईसीआईनेट मंच पर भी अपलोड करने होंगे। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि मृत्यु के मामलों को छोड़कर नाम हटाने के हर प्रस्ताव पर संबंधित मतदाता को व्यक्तिगत नोटिस दिया जाए। दावे और आपत्तियों की सूचियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय और मतदान केंद्रों के सूचना पट्टों पर प्रकाशित करने तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराने के बाद कम से कम सात दिन का स्पष्ट अंतराल रखा जाएगा। इसके बाद ही किसी मामले में निर्णय लिया जा सकेगा। यदि किसी मतदान केंद्र पर प्रस्तावित नाम विलोपन की संख्या कुल मतदाताओं के दो प्रतिशत से अधिक है या एक ही व्यक्ति पांच से अधिक मामलों में आपत्तियां दर्ज कराता है, तो ऐसे मामलों की निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से दोबारा जांच करनी होगी। ये सुरक्षा उपाय एसआईआर को लेकर जारी राजनीतिक टकराव के बीच महत्वपूर्ण हैं। विपक्षी दल लगातार नाम हटाने के पैमाने और प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाते रहे हैं कि वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। आयोग के ताजा निर्देशों का उद्देश्य पुनरीक्षण प्रक्रिया में जवाबदेही बढ़ाना और पात्र नागरिकों को मतदान के अधिकार से वंचित होने से बचाना है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आधार संख्या उपलब्ध नहीं होना मतदाता सूची में नाम शामिल करने का आवेदन खारिज करने या मौजूदा प्रविष्टि हटाने का आधार नहीं हो सकता। फॉर्म–६ और फॉर्म–८ में आधार का विवरण देना स्वैच्छिक रहेगा और केवल आधार संख्या उपलब्ध नहीं कराने के कारण किसी मतदाता का पंजीकरण रोका नहीं जा सकेगा। निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म–६ का इस्तेमाल होगा, जबकि विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाताओं को फ र्म–६ए के जरिए आवेदन करना होगा। प्रस्तावित नाम शामिल करने पर आपत्ति या नाम हटाने के अनुरोध के लिए फॉर्म–७ तथा निवास स्थान बदलने, विवरण में सुधार, मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) बदलने और दिव्यांग मतदाताओं को चिह्नित करने के लिए फॉर्म–८ का उपयोग किया जाएगा। आवेदन मतदाता सेवा पोर्टल या ईसीआईनेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भी जमा किए जा सकेंगे। आयोग ने मतदाताओं की सुविधा और मतदान केंद्रों तक पहुंच आसान बनाने के लिए उनका व्यापक युक्तिकरण करने का भी निर्देश दिया है। सामान्य नियम के तहत किसी मतदान केंद्र पर आयोग की पूर्व अनुमति के बिना १,२०० से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए। मतदान केंद्रों की सीमाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित होनी चाहिए और उनके अधिकार क्षेत्र में कोई ओवरलैप नहीं होना चाहिए। मतदाताओं को अपने निर्धारित मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए दो किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने या प्राकृतिक बाधाएं पार करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बहुमंजिला आवासीय परिसरों, समूह आवासीय सोसाइटियों, शहरी झुग्गी बस्तियों और घनी आबादी वाले इलाकों में विशेष ध्यान देने को कहा गया है, जहां अतिरिक्त मतदान केंद्रों की आवश्यकता हो सकती है। निर्वाचन अधिकारियों को यथासंभव एक ही परिवार के सदस्यों को एक ही अनुभाग और मतदान केंद्र में रखने तथा एक ही इमारत या इलाके के निवासियों को साथ रखने का निर्देश दिया गया है। इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूचियों का विस्तृत सांख्यिकीय आकलन भी किया जाएगा, ताकि पंजीकरण में कमियों की पहचान की जा सके। इसमें विशेष रूप से महिलाओं और १८–१९ वर्ष आयु वर्ग के युवा मतदाताओं पर ध्यान दिया जाएगा। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को लिंग अनुपात, आयु वर्ग, मतदाताओं की संख्या में असामान्य वृद्धि या कमी तथा मतदान केंद्र स्तर पर विसंगतियों की जांच करने को कहा गया है। इसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य स्तर पर आकलन कर सामने आई कमियों को दूर करने के लिए कार्ययोजना तैयार करेंगे। निर्धारित समयसीमा में प्रक्रिया पूरी करने के लिए आयोग ने राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन को पर्याप्त कर्मचारियों और जरूरी संसाधनों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिवों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पुनरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पद रिक्त न रहें। प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन से लेकर अंतिम सूची अधिसूचित होने तक इस प्रक्रिया में लगे अधिकारियों के तबादले के लिए भी आयोग की पूर्व अनुमति जरूरी होगी। इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठकें करने तथा निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को दावे और आपत्तियों की मुद्रित सूचियां साप्ताहिक रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) प्रतिदिन फॉर्म–६, फॉर्म–७ और फॉर्म–८ के अधिकतम १० आवेदन बूथ लेवल अधिकारी को जमा करा सकेंगे। इन आवेदनों का संबंधित अधिकारी सत्यापन करेंगे। आयोग ने प्रवासियों, बेघर लोगों, रैन बसेरों में रहने वालों, श्रमिक बस्तियों और अन्य कमजोर वर्गों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष अभियान और शिविर लगाने को भी कहा है। महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, अनुसूचित जनजातियों, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों का पंजीकरण बढ़ाने के लिए भी विशेष उपाय निर्धारित किए गए हैं। यह निर्देश आयोग की २६ सितंबर को जारी उन हिदायतों के बाद आया है, जिनमें पात्र नागरिकों, विशेषकर मतदाता सूची से छूट गए लोगों तथा युवा और पहली बार मतदान करने वालों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा गया था। वर्ष २०२७ की तीन अतिरिक्त अर्हता तिथियों के लिए अग्रिम आवेदन की सुविधा देकर आयोग ने मतदाता पंजीकरण का दायरा बढ़ाने के साथ ही सत्यापन और गलत तरीके से नाम शामिल करने या हटाने के खिलाफ सुरक्षा उपायों को मजबूत करने का प्रयास किया है। इन छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया २१ जनवरी को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ पूरी होगी।

दिल्ली में इमारत गिरने से दो की मौत

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एक और इमारत गिर गई है, जिसमें दब कर दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हुए है। घटना चांदनी चौक इलाके की है, जहां गुरुवार सुबह एक तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई। दिल्ली फायर सर्विस ने मलबे में दबे कई लोगों के बाहर निकाला। अधिकारियों ने बताया है कि घटना सुबह १० बजे के करीब चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के पास गली सत्तारा में हुई। हादसे की सूचना मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। इसके अलावा एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम की कई टीमें भी राहत और बचाव कार्य में लगीं। दिवाली की खरीदारों की भारी भीड़ की वजह से राहत और बचाव कार्य प्रभावित हुआ। हादसे के बाद एमसीडी ने दो अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनमें असिस्टेंट इंजीनियर (बिल्डिंग) मोहम्मद नईम और जूनियर इंजीनियर (बिल्डिंग) अमन दलाल शामिल हैं। गौरतलब है कि इस साल राजधानी दिल्ली इमारत गिरने का यह छठा बड़ा मामला है। इससे पहले पांच हादसों में २१ लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें सत्य निकेतन और सीमापुरी हादसे शामिल हैं। सत्य निकेतन की घटना में जान गंवाने वालों में कई छात्र थे। बहरहाल, चांदनी चौक की घटना को लेकर एक अधिकारी ने कहा कि इमारत का निर्माण चल रहा था, लेकिन करीब १५ दिन पहले काम रोक दिया गया था। हादसे के समय मजदूर छत के नीचे लगे सपोर्ट सिस्टम को हटा रहे थे। इसी दौरान पूरी इमारत ढह गई।

सीएम योगी की अपील- इस धनतेरस ओडीओपी उत्पादों को दें उपहार, 'लोकल वाली दिवाली' मनाकर बढ़ाएं कारीगरों का सम्मान और रोजगार

लखनऊ। इस धनतेरस अगर आप अपनों को कोई खास उपहार देने की सोच रहे हैं तो इस बार उत्तर प्रदेश की मिट्टी से जुड़े उत्पादों को तरजीह दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि वे इस धनतेरस पर उपहार के रूप में 'एक जिला, एक उत्पाद' (ओडीओपी) योजना के उत्पाद खरीदें और स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों को प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि ओडीओपी योजना के तहत तैयार उत्पादों की खरीदारी करें और स्थानीय कारीगरों व शिल्पकारों को प्रोत्साहित करें।



CM योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ष्धनतेरस पर्व की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी की कृपा से सबके अंतर्मन में संतोष का दीप जले और जीवन प्रेम, प्रसन्नता व आनंद के प्रकाश से आलोकित हो। सभी के जीवन में सुख–समृद्धि, आरोग्यता एवं सौभाग्य का वास हो। सीएम योगी की ओर से एक और पोस्ट में लिखा गया, 'आयुर्वेद के जनक, भगवान धन्वंतरि की जयंती पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बध ाई एवं शुभकामनाएं। भगवान ध न्वंतरि का ज्ञान 'स्वस्थ जीवन ही समृद्ध जीवन' की राह दिखाता है। इस पावन अवसर पर उनसे सभी के लिए आरोग्यता, दीर्घायु एवं यश की कामना है।' मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि स्थानीय उत्पादों की हर खरीदारी कारीगरों के परिवारों के लिए आत्मनिर्भरता और सम्मान का अवसर बन सकती है। स्थानीय उत्पादों की हर खरीदारी किसी कारीगर के परिवार के लिए आत्मनिर्भरता और सम्मान का अवसर बन सकती है। उन्होंने कहा कि भदोही के कालीन, प्रयागराज का मूंज शिल्प, मैनपुरी की तारकशी और चित्रकूट के काष्ठ खिलौने प्रदेश की समृद्ध कला और संस्कृति की पहचान हैं। सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश का निर्यात वर्ष २०१६–१७ के ८४ हजार करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष २०२५–२६ में दो लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि लखनऊ और ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट के साथ भदोही का कार्पेट बाजार प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' विजन का उल्लेख करते हुए लोगों से स्थानीय उत्पादों को अपनाने और 'लोकल वाली दिवाली' मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि इस धनतेरस पर ओडीओपी उत्पादों को उपहार के रूप में देकर 'लोकल वाली दिवाली' मनाएं। इससे स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को रोजगार मिलेगा और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्प को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने प्रदेशवासियों को धन्वंतरि जयंती और धनतेरस की शुभकामनाएं भी दीं। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा, 'आइए, 'लोकल वाली दिवाली' मनाएं और 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। ध न्वंतरि जयंती और धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

डीआरडीओ ने अर्ध–बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का किया सफल परीक्षण

नई दिल्ली। देश में विकसित अर्ध–बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का ओडिशा के तट से गुरुवार को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान (डीआरडीओ) ने बताया कि मिसाइल को ड एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से पूर्वाह्न करीब ११.१० बजे परीक्षण–ल न्च किया गया था। डीआरडीओ ने बताया कि चांदीपुर की इंटिग्रेटेड टेस्ट रेंज की ओर से तैनात किये गये विभिन्न रेंज उपकरणों द्वारा एकत्रित आंकड़ों ने मिसाइल के सफल परीक्षण की पुष्टि की। हैदराबाद स्थित 'रिसर्च सेंटर इमारत' ने अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के सहयोग से 'प्रलय' को स्वदेशी रूप से विकसित किया है। यह भारत की स्वदेशी मिसाइल विकास क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण इजाफा है। इस मिसाइल सिस्टम का निर्माण भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किया है, जो इसके विकास और उत्पादन से जुड़े साझेदारों में से एक है। डीआरडीओ के वरिष्ठ अधिकारियों, रक्षा उद्योग के प्रतिनिधियों और सशस्त्र बलों के सदस्यों ने इस उड़ान परीक्षण को देखा, जो उपयोगकर्ता मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत किया गया था। इस ताजा सफल परीक्षण के साथ, अब यह मिसाइल सिस्टम सशस्त्र बलों में शामिल किए जाने के करीब पहुंच गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ, सशस्त्र बलों और उद्योग भागीदारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक तकनीकों से लैस यह मिसाइल देश की तकनीकी क्षमताओं को और मजबूत करेगी, तथा उभरते खतरों के खिलाफ सेना की तैयारियों को और बेहतर बनाएगी। रक्षा सचिव और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव, राजेश कुमार सिंह ने भी इस सफल उड़ान परीक्षण में शामिल टीमों को बधाई दी।

एलडीएः दीवाली से पहले २,२४३ परिवारों को लॉटरी से मिले भूखण्ड

लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधि ाकरण द्वारा दीवाली से पहले नैमिष नगर और वरुण विहार योजना के आवेदकों के मध्य भूखण्डों का आवंटन किया गया। बुधवार को दोनों योजनाओं के प्रथम चरण के २,२४३ भूखण्डों का लॉटरी से आवंटन किया गया। अपने नाम की पर्ची खुलते ही किसी का चेहरा खिल उठा तो किसी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आये। अब बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार को अन्य श्रेणी के भूखण्डों की लॉटरी निकाली जाएगी। इस मौके पर अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा एवं सी०पी० त्रिपाठी, संयुक्त सचिव सोमकमल सीताराम, उप सचिव माधवेश कुमार, प्रभारी अधिकारी–योजना रवि नंदन सिंह एवं विशेष कार्याधिकारी राजीव कुमार समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचकर लॉटरी कार्यक्रम का जायजा लिया। उन्होंने लॉटरी की पूरी प्रक्रिया एवं आवेदकों के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए पारदर्शिता के साथ आवंटन प्रक्रिया संपन्न कराने के निर्देश दिए। साथ ही, लॉटरी में उपस्थित सभी आवेदकों को शुभकामनाएं दीं। वहीं, एलडीए के सचिव सुशील प्रताप सिंह ने भी लॉटरी कार्यक्रम पहुंचकर व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने संबंधि ात अधिकारियों से आवंटन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की तथा पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष, सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सफल आवेदकों को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दीं। अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि बुधवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर सभागार में वरुण विहार योजना के प्रथम चरण की लॉटरी ड्रॉ का आयोजन किया गया। पहले दिन ११२.५ वर्गमीटर क्षेत्रफल के १,५२२ भूखण्डों का लॉटरी से आवंटन किया गया। अब बृहस्पतिवार को २०० वर्ग मीटर के ६१७ एवं शुक्रवार को १६२, २८८, ३०० एवं ४५० वर्ग मीटर क्षेत्रफल के ७२७ भूखण्डों का ल टरी ड्र किया जाएगा। अपर सचिव सी०पी० त्रिपाठी ने बताया कि बुधवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स हॉल में नैमिष नगर योजना के प्रथम चरण की लॉटरी ड्रॉ का आयोजन किया गया। पहले दिन ७२ वर्ग मीटर क्षेत्रफल के १६७ एवं ११२.५ वर्ग मीटर क्षेत्रफल के ५२४ भूखण्डों का लॉटरी से आवंटन किया गया। अब बृहस्पतिवार को १६२ एवं २०० वर्ग मीटर के ८१६ एवं शुक्रवार को २८८ एवं ४५० वर्ग मीटर क्षेत्रफल के १३३ भूखण्डों का लॉटरी ड्रॉ किया जाएगा। नैमिष नगर और वरुण विहार योजना के भूखण्डों के लिए २४ सितंबर से २७ अक्टूबर, २०२६ के मध्य ऑनलाइन पंजीकरण खोला गया था। दोनों योजनाओं में कुल ३८,४५७ लोगों ने पंजीकरण कराया है। बुधवार को लॉटरी के पहले दिन दोनों योजनाओं के २,२४३ भूखण्डों का लकी ड्रॉ खोला गया। जिसमें खुले मंच पर आवेदकों को बुलाकर उन्हीं के हाथों से लॉटरी ड्रॉ की पर्चियां निकलवायी गयी।

जीसीआरजी इंटरनेशनल स्कूल ने जीती द्वितीय केएन सिंह मेमोरियल ट्रॉफी

लखनऊ। द्वितीय स्वर्गीय केएन सिंह मेमोरियल अंडर–१६ अंतरविद्यालयी क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन काल्विन तालुकेदार्स कॉलेज और जीसीआरजी इंटरनेशनल स्कूल के बीच खेले



गए रोमांचक फाइनल मुकाबले के साथ हुआ। जीसीआरजी इंटरनेशनल स्कूल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए काल्विन तालुकेदार्स कॉलेज को २२ रनों से पराजित कर प्रतियोगिता की विजेता ट्रॉफी अपने नाम की। समापन समारोह में केजीएमयू के यूरोल जी विभागाध्यक्ष डॉ. अपुल गोयल मुख्य अतिथि और क्रिकेट एसोसिएशन आफ लखनऊ अभिजीत सिन्हा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आयोजन संस्था विवेकानंद मॉडर्न एकेडमी के अध्यक्ष पूर्व आईपीएस उमेश कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जीसीआरजी इंटरनेशनल स्कूल ने १५ ओवरों में ७ विकेट के नुकसान पर १३७ रन बनाए। आयुष ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए ३६ गेंदों पर ५७ रन बनाए। काल्विन की ओर से सक्षम मिश्रा ने सर्वाधिक ४ विकेट प्राप्त किए। लक्ष्य का पीछा करते हुए काल्विन तालुकेदार्स क लेज की टीम ने संघर्षपूर्ण खेल दिखाया, लेकिन ६ विकेट पर ११० रन ही बना सकी। विजेता टीम की ओर से रितिक सिंह और मनीष यादव ने २–२ विकेट लिए। विजेता जीसीआरजी इंटरनेशनल स्कूल को २० हजार तथा उपविजेता काल्विन तालुकेदार्स कॉलेज को १० हजार की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की गई। प्रत्येक व्यक्तिगत पुरस्कार विजेता को पांच हजार रुपये की नकद राशि प्रदान की गई। इस प्रतियोगिता में कुल १२ विद्यालयों विवेकानंद मॉडर्न एकेडमी, लखनऊ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, जीसीआरजी इंटरनेशनल स्कूल, एसआर इंटरनेशनल स्कूल, काल्विन तालुकेदार्स कॉलेज, मान्ट फोर्ट इंटर कॉलेज, साहू इंटरनेशनल स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल एक्सटेंशन, सीएमएस गोमती नगर, सेंट क्लेयर्स कॉन्वेंट स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल एल्डिको तथा एस. आर. ग्लोबल स्कूल शामिल रहे। यह प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे विवेकानंद मॉडर्न एकेडमी के संस्थापक केएन सिंह की स्मृति में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना, अनुशासन, टीम भावना एवं उत्कृष्ट खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करना था। प्रतियोगिता का सफल आयोजन युवा खिलाड़ियों के उत्साह और खेल प्रतिभा का प्रेरणादायक उदाहरण बना।

मानव संपदा पोर्टल पर ई-सर्विस बुक में संशोधन के लिए २५ नवंबर तक की समयसीमा तय

लखनऊ।'' उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने मानव संपदा पोर्टल पर पंजीत अधिकारियों, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की ई–सर्विस बुक में संशोधन एवं डाटा अपडेट करने के लिए २५ नवंबर २०२६ तक की समयसीमा निर्धारित की है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षा निदेशालय की ओर से ५ नवंबर को आदेश जारी किया गया है। आदेश में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों, वित्त एवं लेखाधिकारियों तथा खंड शिक्षा अधिकारियों को अभियान चलाकर निर्धारित समय में संशोधन की प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों की ई–सर्विस बुक से संबंधित प्रविष्टियां संबंधित कार्यालयों की ऑफिस एडमिन आईडी के माध्यम से स्थापित डाटा एंट्री, वेरिफिकेशन और करेक्शन आईडी के जरिए की गई हैं। एक जनवरी २०२५ से संचालित ई–सर्विस बुक करेक्शन मॉड्यूल पर बड़ी संख्या में त्रुटि सुधार के मामले सामने आने के बाद विभाग ने डाटा फीडिंग में लापरवाही और अपूर्ण प्रविष्टियों पर नाराजगी जताई है। विभाग ने निर्देश दिया है कि मानव संपदा पोर्टल पर पंजीत अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पैन कार्ड, अवकाश और आधार विवरण को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के संशोधन एवं अपडेशन की कार्रवाई २५ नवंबर तक पूरी कर ली जाए। इसके लिए संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी। वहीं, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पैन कार्ड, अवकाश और आधार संबंधी संशोधन पहले की तरह जनपदों से ई–मेल के माध्यम से प्राप्त अनुरोध के आधार पर निदेशालय स्तर से किए जाएंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि २५ नवंबर २०२६ के बाद मानव संपदा पोर्टल पर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के सेवा अभिलेख में त्रुटि पाए जाने पर संबंधित अवधि में कार्यरत अ फिस एडमिन आईडी धारक कार्यालयाध्यक्ष को जिम्मेदार माना जाएगा। ऐसे मामलों में उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत करेक्शन आईडी सक्रिय रहने की अवधि में ई–सर्विस बुक करेक्शन म ड्यूल का संचालन स्थगित रहेगा। पहले से आवेदन किए गए और लंबित मामलों का निस्तारण भी जारी आदेश में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों में पंजीत कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का सत्यापन कर समयसीमा के भीतर संशोधन सुनिश्चित कराने को कहा है। साथ ही अपूर्ण या गलत डाटा फीडिंग के लिए जिम्मेदार डाटा एंट्री, वेरिफिकेशन और करेक्शन आईडी संचालित करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर निदेशालय को इसकी जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस आदेश से प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की ई–सर्विस बुक में दर्ज विवरणों को दुरुस्त करने की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।

सीएम योगी ने ४,५४३ नवचयनित उपनिरीक्षकों को सौंपे नियुक्ति पत्र, यूपी पुलिस को मिली नई ताकत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस को ४५४३ नए उपनिरीक्षक मिल गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को पुलिस लाइन लखनऊ में आयोजित समारोह में उपनिरीक्षक



(नागरिक पुलिस) एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–२०२५ में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस भर्ती के जरिए नागरिक पुलिस, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल और महिला बटालियनों को नए अधिकारी मिले हैं। भर्ती के तहत नागरिक पुलिस के ४२४२ उपनिरीक्षकों का चयन हुआ है। इनमें ३३६४ पुरुष और ८४८ महिला उपनिरीक्षक शामिल हैं। इसके अलावा पीएसी के लिए १३५ प्लाटून कमांडर, विशेष सुरक्षा बल (एसएसएफ) के लिए ६० प्लाटून कमांडर और महिला बटालियनों के लिए १०६ महिला उपनिरीक्षकों का चयन किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने १२ अगस्त २०२५ को कुल ४५४३ पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इन पदों के लिए १५,७५,७६० अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। लिखित परीक्षा १४ और १५ मार्च २०२६ को आयोजित की गई। इसमें रिक्त पदों के सापेक्ष २.७ गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। इसके बाद चयन प्रक्रिया के अगले चरण में १५ से १७ जून तक अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण कराया गया। वहीं, २६ जून से चार जुलाई तक शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की गई। भर्ती बोर्ड ने १४ जुलाई को अंतिम चयन परिणाम घोषित किया था। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत नवगठित विशेष सुरक्षा बल के लिए ६० उपनिरीक्षकों के साथ १,३४१ आरक्षियों का भी चयन किया गया है। वहीं, तीन महिला बटालियनों के लिए १०६ महिला उपनिरीक्षकों और २,२८२ महिला आरक्षियों का चयन हुआ है। नियुक्ति पत्र वितरण के साथ चयनित अभ्यर्थियों की उत्तर प्रदेश पुलिस में नई जिम्मेदारी की शुरुआत होगी।

सुरों की सरिता में देर रात तक सराबोर रहा दशहरा मेला, उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों का हुआ सम्मान

लखीमपुर। ऐतिहासिक दशहरा मेला केवल आस्था, परंपरा और मनोरंजन का उत्सव नहीं, बल्कि सामाजिक सरोकारों, सांस्कृतिक चेतना और प्रतिभाओं के सम्मान का भी सशक्त मंच बनता जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शृंखला में चौदहवें दिन आयोजित आमंत्रित कलाकारों का संगीत सम्मेलन सुरों, साज और संगीत की ऐसी मनमोहक महफिल लेकर आया, जिसमें देर रात तक पूरा पंडाल संगीत की मस्ती में झूमता रहा। कलाकारों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और करतल ध्वनि से पूरा परिसर गूंजता रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा ड. इरा श्रीवास्तव, अधिशासी अधिकारी संजय कुमार, विशिष्ट अतिथि अजमानी पब्लिक स्कूल की प्रबंधक गुरजीत अजमानी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष आशू मिश्रा एवं जिला मंत्री शरद मिश्रा ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उद्घाटन सत्र का प्रभावशाली संचालन पूर्ववत समाजसेवी एवं साहित्यकार राममोहन गुप्त 'अमर' ने किया। संगीत की सुरमयी शाम सामाजिक एवं रचनात्मक योगदान देने वाली विभूतियों के सम्मान के नाम भी रही। भाजपा जिला कार्यालय प्रभारी अभिजात मिश्रा, डॉ. हरिओम बाजपेई, कलमकार अनिल कुमार श्रीवास्तव एवं शिखर पुरी को अपने–अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए विशेष सम्मान प्रदान किया गया। वहीं पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति संवर्धन की दिशा में निरंतर प्रेरणादायी प्रयास कर रहे नगर के प्रतिष्ठित पर्यावरण मित्र समूह को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। सम्मानित पर्यावरण मित्रों में विशाल सेठ, राममोहन गुप्त श्अमरश्, मयूरी नागर, संजय गुप्ता, सपना कक्कड़, रश्मि महेंद्र, सुमन श्रीवास्तव एवं मधुलिका त्रिपाठी शामिल रहे। यह सम्मान उन निस्वार्थ प्रयासों की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति रहा, जो प्रेंति को हरा–भरा बनाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण का सपना साकार करने में जुटे हैं। सम्मान समारोह के उपरांत जिला पंचायत सदस्य इंजीनियर दुर्गेश वर्मा के संयोजन में आयोजित संगीत सम्मेलन ने अपनी पूरी रंगत बिखेरी। तरन्नुम मलिक जैन तथा यासूब अली एंड पार्टी, मुंबई के कलाकारों ने अपनी मनमोहक और सम्मोहक प्रस्तुतियों से संगीत प्रेमियों का दिल जीत लिया। सुरों की मिठास, आवाज का जादू और कलाकारों की शानदार प्रस्तुति ने श्रोताओं को देर रात तक अपनी जगह से बांधे रखा। पंडाल में उमड़ी बेतहाशा भीड़ के बीच हर प्रस्तुति पर तालियों की गड़गड़ाहट और दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता था। संगीत और श्रोताओं के बीच बना यह आत्मीय जुड़ाव कार्यक्रम की सफलता की कहानी स्वयं बयां कर रहा था। कार्यक्रम के संयोजक मंडल में शमीम बानो, निगार अली, डॉ. एजाज अहमद, नीलम रस्तोगी एवं राशिद खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर मेला अध्यक्ष रवींद्र रावत, मेलाधिकारी समरा सईद, हरि प्रकाश त्रिपाठी, बजरंग शर्मा, श्वेता शर्मा, चंद्र प्रकाश धुरिया, राकेश कुमार, पारस मौर्या, मनोज राज, विक्रम गुप्ता, सर्वेश वर्मा, सुरेंद्र मौर्या सहित अनेक गणमान्य नागरिक, समाजसेवी एवं संगीत प्रेमी उपस्थित रहे। सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के साथ प्रतिभाओं को पहचान और समाजसेवियों को सम्मान देने की यह परंपरा ऐतिहासिक दशहरा मेले को महज एक आयोजन नहीं, बल्कि नगर की सामूहिक सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक एकजुटता का जीवंत उत्सव बना रही है।



खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ उद्घाटन

(हरिशंकर मिश्र)

लखीमपुर खीरी। राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र देउवापुर लखीमपुर द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिला/ पुरुषों को १०० दिवसीय उद्यमिता



विकास(SCP) खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन संदीप वर्मा जिला पंचायत सदस्य व संजय कुमार वर्मा प्रतिनिधि श्रीमती कांति सिंह एमएलसी के द्वारा फीता काटकर व मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया गया तथा परीक्षार्थियों में लेखन सामग्री एवं बैग वितरित किए गए। संदीप वर्मा ने प्रशिक्षार्थियों को कौशल युक्त बनाकर अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं तथा अन्य लोगों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं जिससे लोगों को गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती संजय वर्मा प्रतिनिधि श्रीमती कांति सिंह (एमएलसी) ने बताया मार्केट में बहुत सारे उत्पाद बिक रहे हैं वैसे अपना भी ब्रांड बनाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं केंद्र प्रभारी राजेश कुमार पिप्पल ने १०० दिवसीय उद्यमिता विकास खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी जिसमें मौसमी फल एवं सब्जियों के संरक्षण की लिखित एवं प्रयोगात्मक जानकारी प्रदान की जाएगी।

प्रयागराज में २२० करोड़ से बनेगा १० मेगावाट का डेटा सेंटर, एयरटेल एनएक्सट्रा लगाएगी ४.४३ एकड़ में यूनिटय ३०० को मिलेगा रोजगार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर के क्षेत्र में एक और बड़ी परियोजना का रास्ता साफ हुआ है। प्रयागराज की सरस्वती हाईटेक सिटी में १० मेगावाट क्षमता का डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने पांच नवंबर को मेसर्स एयरटेल एनएक्सट्रा प्राइवेट लिमिटेड को लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) जारी किया है। परियोजना के लिए कंपनी को ४.४३ एकड़ भूमि आवंटित किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। भारती एयरटेल समूह की डेटा सेंटर क्षेत्र की कंपनी इस परियोजना में करीब २२० करोड़ रुपये का निवेश करेगी। परियोजना के धरातल पर आने से लगभग ३०० लोगों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। इसके साथ प्रयागराज में सूचना



प्रौद्योगिकी आधारित गतिविधियों और सहायक सेवाओं को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. बलकार सिंह ने कहा कि प्रयागराज के सरस्वती हाईटेक सिटी में प्रस्तावित १० मेगावाट डेटा सेंटर आधुनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे प्रयागराज को डेटा सेंटर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित गतिविधियों के उभरते केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि परियोजना से डेटा स्टोरेज, क्लाउड सेवाओं और डिजिटल तकनीक से जुड़ी औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही तकनीकी और सहायक सेवाओं से जुड़े स्थानीय कारोबार के लिए भी नए अवसर खुलेंगे। एयरटेल एनएक्सट्रा देश में हाइपरस्केल और एज डेटा सेंटर का नेटवर्क संचालित करती है। कंपनी उद्यमों और क्लाउड सेवा प्रदाताओं समेत विभिन्न संस्थानों को डेटा सेंटर सेवाएं उपलब्ध कराती है। प्रयागराज में उसके प्रस्तावित निवेश को प्रदेश में डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े औद्योगिक आधार के विस्तार के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

पड़ोसी की प्रताड़ना से नाबालिग ने दी जान, मलिहाबाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को दबोचा, चौकी इंचार्ज पर गिरी गाज!!

लखनऊ। लखनऊ के मलिहाबाद इलाके के रमगढ़ा गांव में एक नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना २ नवंबर की सुबह करीब ११ बजे की है। सूचना



मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लड़की के परिवार ने थाने में शिकायत दी। शिकायत के बाद पुलिस ने हंस कुमार, उसके भाई विनय, पिता श्याम सुंदर और मां राम लल्ली के खिलाफ केस दर्ज किया है। परिवार का आरोप है कि हंस कुमार लड़की को डराता था, धमकाता था और जबरदस्ती अपने साथ चलने के लिए कहता था। परिवार ने बताया कि करीब ५ महीने पहले भी इन्हीं लोगों ने लड़की के पिता राम लखन को मारा–पीटा था। दोनों परिवार पड़ोसी हैं और रिश्तेदारी में भी हैं। इस मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई पुलिस के अपने ही कर्मचारी पर हुई है। परिवार ने कहा था कि पहले मारपीट की शिकायत कसमंडी कला चौकी पर की थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। इस लापरवाही की जांच एसीपी मलिहाबाद ने की। जांच में चौकी इंचार्ज विवेक कुमार दोषी मिले। इसके बाद डीसीपी नॉर्थ ने उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है। मुख्य आरोपी हंस कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

'रामायणम्' ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, पहले दिन दुनियाभर में कमाए १५५ करोड़ रुपये

मुम्बई। फिल्म 'रामायणम्' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत करते हुए इतिहास रच दिया है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी और नमित मल्होत्रा द्वारा निर्मित इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन दुनियाभर में १५५ करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है। इसके साथ ही यह दिवाली से पहले



रिलीज होने वाली भारतीय फिल्मों में अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है। प्राइम फोकस स्टूडियो और र किंग स्टार यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के बैनर तले निर्मित 'रामायणमृ पार्ट वन' पांच नवंबर २०२६ को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में हैं। फिल्म के जरिए भारतीय संस्कृति की सदियों पुरानी महागाथा को भव्य सिनेमाई स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म की १५५ करोड़ रुपये की वैश्विक ओपनिंग को दिवाली से पहले भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी शुरुआत बताया जा रहा है। इससे पहले दिवाली के आसपास रिलीज हुई फिल्मों के लिए पहले दिन का सर्वाधिक अखिल भारतीय नेट कलेक्शन ४० करोड़ रुपये और दुनियाभर का ग्रॉस कलेक्शन ६४ करोड़ रुपये रहा था। आमतौर पर दिवाली से ठीक पहले का समय फिल्मों की रिलीज के लिहाज से चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इस दौरान लोग घरों की साफ–सफाई, सजावट, खरीदारी और त्योहार की तैयारियों में व्यस्त रहते हैं। इसके कारण सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या प्रभावित होती है। हालांकि, 'रामायणम्' ने इस ध ारणा को तोड़ते हुए पहले ही दिन दर्शकों को बड़ी संख्या में सिनेमाघरों तक खींचने में सफलता हासिल की। फिल्म को लेकर दर्शकों के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शुरुआती शोज से ही सिनेमाघरों में अच्छी भीड़ देखने को मिली। दिवाली का त्योहार अभी बाकी है और फिल्म ने उससे पहले ही ब क्स अ फिस पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में इसके कारोबार में और तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

बचपन की पारंपरिक दिवाली को याद करती हैं अभिनेत्री सिमरन कौर

मुम्बई। अनमोल टीवी के धारावाहिक 'हमारी राधा' में मुख्य भूमिका निभा रहीं अभिनेत्री सिमरन कौर ने दिवाली से जुड़ी अपने बचपन की यादें साझा करते हुए कहा कि परिवार और पड़ोसियों के साथ पारंपरिक तरीके से त्योहार मनाने का अपनापन आज भी उन्हें याद आता है। दिवाली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस अवसर पर पूजा–पाठ, पकवान, नए कपड़े और पारिवारिक परंपराओं का विशेष महत्व होता है। 'हमारी राधा' में राधा का किरदार निभा रहीं सिमरन कौर इन दिनों धारावाहिक में रिश्तों के बदलते समीकरणों के बीच संघर्ष करती नजर आ रही हैं। पति गिरधर के धोखे से आहत राधा अब अपने लिए खड़े होने और उसे वापस पाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में दर्शकों के मन में यह सवाल है कि क्या इस दिवाली राधा को अपने पति के साथ त्योहार मनाने का अवसर मिलेगा। अपने बचपन की यादें साझा करते हुए सिमरन कौर ने बताया कि उनकी मां और मौसियां दिवाली से कई दिन पहले ही गुजिया और चकली बनाने की तैयारियां शुरू कर देती थीं। पूरा मोहल्ला मिलकर त्योहार के पकवान तैयार करता था। लक्ष्मी पूजा, रिश्तेदारों के घर जाना, बड़ों का आशीर्वाद लेना और उनसे शगुन मिलना उनके लिए दिवाली के सबसे खास पल हुआ करते थे। उन्होंने कहा



कि आज दिवाली मनाने का अंदाज भले ही अधिक भव्य और चमक–दमक भरा हो गया है, लेकिन परिवार के साथ घर पर त्योहार मनाने की गर्मजोशी और अपनापन आज भी बेमिसाल है। वह कहीं भी रहें, बचपन की सादगी भरी परंपराओं और अपनों के बीच दिवाली मनाने के एहसास को हमेशा याद करती रहेंगी। 'हमारी राधा' का प्रसारण हर दिन रात ९:३० बजे अनमोल टीवी पर किया जाता है।

हमारे अन्य प्रतिनिधि
संजय बाजपेई
सीतापुर
मो.9935160370
प्रियंका त्रिपाठी
नई दिल्ली
विधिक सलाहकार
सुरेश नारायण मिश्र
क्षेत्रीय सम्पादक
सौरभ कुमार, बिहार
मो.09386075289
मो० अरशद
ब्यूरो चीफ
मऊ

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।
आर.एन.आई
UPHIN/2010/32566

सम्पादक
आरती पाण्डेय
मो.9415087228
9889745884. 9807059191.
9026560178

Email-
adbhutsamachar
@yahoo.in
adbhut_samachar
@rediffmail.com
सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक